

न्यायालय जिला कलक्टर, पाली  
पीठासीन अधिकारी: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

प्रकरण संख्या :: 1/2025  
जीसीएमएस नम्बर :: 2025/5

अपीलाण्ट :-

बनाम

रेस्पोजेण्ट्स :-

श्रीमती मशरी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री भुराराम जाति घांची निवासी- ग्राम 49 घांचियों का बास, बाला, तहसील पाली, जिला पाली।

1. श्री नेमाराम पुत्र श्री भूराराम,
2. कमली पत्नी नेमाराम जाति घांची ग्राम 49 घांचियों का बास, बाला, तहसील पाली जिला पाली
3. उपखण्ड अधिकारी पाली

प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 16 माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007

उपस्थिति :-



अपीलाण्ट उपस्थित।  
रेस्पोजेण्ट्स उपस्थित।  
-:: निर्णय ::-

दिनांक :- 12.02.2025

अपीलाण्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 16 माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 तहत विरुद्ध उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पाली के प्रकरण संख्या 03/2024 बअनवान मशरी देवी बनाम नेमाराम वगैरह में आदेश दिनांक 18.11.2024 को निरस्त कराने हेतु पेश किया गया है। अपीलाण्ट का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोजेण्ट्स को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलाण्ट व रेस्पोजेण्ट्स वक्त बहस उपस्थित हुए। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अपीलाण्ट ने अपील-मीमो में वर्णित कथनों को दोहराते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी पाली ने अपने न्यायालय के प्रकरण संख्या 03/2024 में पारित निर्णय दिनांक 18.11.2024 में आदेश पारित करते हुए अपीलाण्ट के भरण पोषण बाबत प्रत्येक माह मात्र 2000 रुपये निर्धारित किये जो पूर्णतया विधि विरुद्ध है। रेस्पोजेण्ट्स संख्या 01 जो कि अपीलाण्ट का पुत्र है व रेस्पोजेण्ट्स संख्या 02 जो अपीलाण्ट की पुत्रवधु है ये अपीलाण्ट के ही मालिकाना शुदा रहवासीय मकान में रहते हैं वे न तो अपीलाण्ट को उक्त मकान में रहने देते हैं व मकान से बेदखल करते हैं व रेस्पोजेण्ट्स संख्या 02 द्वारा रोज अपीलाण्ट के साथ मारपीट की जाती है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र भरण पोषण हेतु 2000 रुपये की राशि निर्धारित की है जो पूर्णतया विधि विरुद्ध है। अतः अपीलाण्ट के विरुद्ध जो अधीनस्थ न्यायालय ने 2000 रुपये की मासिक भरण-पोषण राशि का आदेश पारित किया गया है उसे प्रत्येक माह 10000 रुपये निर्धारित किया जावे व रेस्पोजेण्ट्स को अपीलाण्ट की मालिकाना शुदा रहवासीय सम्पत्ति व मकान से बेदखली के आदेश फरमावे।

रेस्पोजेण्ट्स संख्या 02 ने अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि वे अपीलाण्ट की सेवा चाकरी करने हेतु तैयार व उसके पति रेस्पोजेण्ट्स संख्या 01 मानसिक बीमार होने से वह मासिक भरण-पोषण जो राशि निर्धारित की गई है वह अदा कर पाने में सक्षम नहीं है। अतः अपील-अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज फरमावे।

प्रकरण में अपीलाण्ट व रेस्पोजेण्ट्स को सुना गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रकरण में रेस्पोजेण्ट्स संख्या 01

पुत्र जिस भवन में रहता है वह भवन उनकी माता के नाम है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक अपीलान्ट के रेसपो. के उक्त मकान से बेदखली के आदेश पर कोई निर्णय नहीं किया है तथा भरण-पोषण राशि भी 2000 रुपये ही तय की है उसे लेकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि एक वृद्ध माता जिसकी आयु 72 वर्ष है उसे सिर्फ 2000 रूपया महीना भरण-पोषण कदापि पर्याप्त नहीं है। अतएव अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2024 को अपास्त करते हुए भरण-पोषण राशि निर्णय दिनांक से 5000 रुपये प्रतिमाह किया जाता है। यह राशि रेसपोडेण्ट संख्या 01 व 02 प्रति माह 5 तारीख तक अपीलान्ट को अदा करेंगे।

प्रकरण में यह भी प्रकट आया कि रेसपो. संख्या 01 नेमाराम जो कि अपीलान्ट के पुत्र है उनका मानसिक इलाज चल रहा है, परन्तु यह भी स्पष्ट श्री नेमाराम व उनकी पत्नी रेसपो. संख्या 02 द्वारा उनकी माता से सद्भावनापूर्वक व्यवहार नहीं किया जाता है। इसलिए माता ने पुत्र के विरुद्ध भरण-पोषण का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है एवं उसके द्वारा मारपीट के भी कथन एवं फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत किये हैं। माता आवेदक अपीलान्ट के नाम जारी पट्टेशुदा मकान में विपक्षी रेसपो. संख्या 01 व उसकी पत्नी रहते हैं एवं अपनी माता के मकान में रहने के बावजूद उसके द्वारा किया जाने वाला सद्भावनापूर्वक व्यवहार नहीं होने के प्रारम्भिक साक्ष्य के आधार पर तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय की न्यायिक नजीर डी. बी. स्पेशल रिट संख्या 920/2019 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि माता-पिता की वह सम्पत्ति चाहे सशर्त उपहार में विलेख दी गई हो अथवा संबंधित कानून में धारा 23 में वर्णित प्रावधान जिसमें यह वर्णित किया गया है कि "by way of gift or otherwise" में "otherwise" को माननीय न्यायालय ने यह परिभाषित किया गया है कि "otherwise" का आशय पुत्र के पास हस्तान्तरण से संबंधित है जिसमें कब्जा भी शामिल है, अर्थात् पुत्र सिर्फ कब्जे के आधार भी माता के मकान में रहता है तो भी उसका दायित्व है कि वह भरण-पोषण करे अन्यथा उसकी उस मकान से जो माता-पिता के नाम है उससे बेदखली की जा सकती है।

प्रकरण में न्यायालय क्योंकि पुत्र मानसिक बीमारी से पीड़ित है तो नरम रूख रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.11.2024 को अपास्त करते हुए भरण-पोषण राशि 2000 रुपये के स्थान पर 5000 रुपये करते हुए न्यायालय हाजा यह भी आदेश देना उचित समझता है कि रेसपोडेण्ट विपक्षी निर्धारित भरण-पोषण राशि तीन माह की अवधि में पुराना arrear एवं प्रतिमाह की राशि निरन्तर अपीलान्ट को देता रहे तथा यदि अपीलान्ट बताये कि रेसपोडेण्ट उसके साथ सद्भावनापूर्वक व्यवहार करे तो उसे अपीलान्ट के मकान में रहने दिया जाये अन्यथा तीन माह की अवधि के बाद विचारण न्यायालय अपीलान्ट के प्रार्थना-पत्र पर रेसपो. विपक्षीगण को, मुआवजा भुगतान नहीं किये जाने पर वसूली एवं बेदखली की कार्यवाही तथा सद्भावना नहीं रखे जाने एवं सेवा-सुश्रुषा नहीं किये जाने पर भी बेदखली की कार्यवाही सुनिश्चित करे। उपर्युक्त निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.11.2024 अपास्त करते हुए भरण-पोषण राशि वृद्धि एवं सशर्त बेदखली के आदेश जारी किये जाते हैं। तदनुसार पालना हो। निर्णय की सत्यप्रति उभयपक्ष को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय

में सुनाया गया।



(एल.एन. मंत्री)  
जिला कलेक्टर, पाली  
जिला कलेक्टर, पाली